www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 337 | जौनपुर, मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

एनडीए की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन, पीएम मोदी ने सांसदों को किया संबोधित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन मंगलवार को संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) में शुरू हुई। यह बैठक लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने के एक दिन बाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ अन्य एनडीए सांसद बैठक में शामिल होने के लिए जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम पहुंचे। पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे एनसीपीआई सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष भी इस बैठक में शामिल हुए। एनडीए नेताओं की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई, जब केंद्र सरकार नकल विरोधी विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वहीं, विपक्ष जंतर–मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित श्पुलिस की ज्यादतीश के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह विधेयक सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। इस दौरान विपक्ष लगातार जोरदार नारेबाजी कर रहा था। इस विधेयक के जरिये सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन का मकसद सख्त कानूनी प्रावधानों के जरिये परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके प्रमुख प्रावध ानों में कड़ी सजा शामिल है, जिसमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति जब्त करना और यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाना शामिल है कि फैसले तीन महीने के भीतर दिए जाएं। श्मंगल मिलनश बैठक वास्तव में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का बदला हुआ नाम है। इसका मकसद रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा देना और गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना है। संसद सत्र के दौरान रोजाना सदन की रणनीति तैयार करने और अलग–अलग दलों के बीच सहमति बनाने के अलावा, श्मंगल मिलनश बैठक एनडीए के सहयोगी

दलों के साथ समन्वय बढ़ाने का माध यम भी है। यह बैठक एनडीए सांसदों की बहस में भागीदारी बढ़ाने और प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं को बोलने का समय और जिम्मेदारी तय करने में मदद करती है। इसमें शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों के सहयोगी नेता शामिल होते हैं। मंगल मिलन बैठक में शामिल होने के बाद एनसीपीआई की सांसद काकोली घोष ने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को एनडीए के हिस्से के रूप में मान्यता मिल गई है। घोष ने बताया कि नवगठित एनसीपीआई ने लोकसभा अध्यक्ष के पास औपचारिक मान्यता के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि सदन में बैठने की व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया अभी चल रही है। काकोली घोष ने कहा, एनसीपीआई पहले से ही चुनाव आयोग में पंजीकृत है। हमने अपनी मान्यता के लिए सभी दस्तावेज लोकसभा अध्यक्ष को दे दिए हैं और उन्होंने हमें एनडीए के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। इसी वजह से आज हमें बैठक में बुलाया गया था। हालांकि, बैठने की व्यवस्था और आगे की मान्यता को लेकर बातचीत जारी है। जैसे ही कुछ तय होगा, हम आपको बताएंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक की तारीफ करते हुए एनसीपीआई नेता ने गठबंधन के सदस्यों के बीच सकारात्मक माहौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने इससे पहले कभी ऐसी बैठक नहीं देखी थी। 2014 से पहले ऐसी बैठकें होती भी नहीं थीं। इसलिए हमें यह बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला और हम एनडीए का हिस्सा बने। एनसीपीआई के सभी सांसद मिलकर काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात है। वहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के बाद एनसीपीआई सांसद सायोनी घोष ने बैठक को जानकारी से भरपूर बताया। उन्होंने छात्र प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार की ओर से लाए गए।

संक्षिप्त खबरें

कांवड़ शिविरों के लिए दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने बड़े कांवड़ शिविरों के लिए वित्तीय सहायता मौजूदा 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने और 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान के मुताबिक, सरकार ने कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और कांवड़ शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इससे कांवड़ समितियां श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में छह से 12 दिन तक संचालित होने वाले कांवड़ शिविरों को मिलने वाली सहायता 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र वाले तीन से पांच दिन के शिविरों के लिए सहायता राशि छह लाख रुपये से बढ़ाकर नौ लाख रुपये की जाएगी। उनके मुताबिक, यह निर्णय कांवड़ समितियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य सभी श्रेणियों के कांवड़ शिविरों की सहायता राशि में भी वृद्धि की जाएगी।

पूर्व राज्यसभा सदस्य अख्तर हसन रिजवी को मुंबई की अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत

मुंबई, (एजेंसी)। यहां की एक अदालत ने कथित धोखाध ाड़ी और जालसाजी के एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य अख्तर हसन रिजवी को सोमवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वह इस अपराध में गहराई से शामिल हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी है और हिरासत में उससे पूछताछ आवश्यक है। कारोबारी रिजवी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता के परिवार की निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें धोखा देने के इरादे से संपत्ति के झूठे और जाली दस्तावेज तैयार किए। पुलिस के मुताबिक, संपत्ति की वास्तविक मालकिन, हाजानी नूरबीबाई कालू का 26 अप्रैल, 1971 को निधन हो गया था। उसने बताया कि कालू की मौत के बाद रिजवी ने कथित तौर पर संपत्ति हड़पने के लिए एक 'एक अन्य महिला' को पेश किया, जिसने मृतका के स्थान पर संपत्ति विलेख पर हस्ताक्षर किया।

विपक्ष के हंगामे से लोकसभा कार्यवाही स्थगित, पेपर लीक बिल पर टिकी नजर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंगलवार को विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण लोकसभा लिए स्थगित कर दी गई। सदन में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने 20 जुलाई के जंतर–मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर शोर–शराबा जारी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र की शुरुआत ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल विजेताओं की तारीफ से की। इसके तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने सदस्यों से अपील की कि वे प्रश्नकाल में बाधा न डालें और दोपहर 2 बजे 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में सहयोग करें, लेकिन हंगामा कम नहीं हुआ। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा बिल पेश करने के बाद भी सदन में अफरा–तफरी मची रही थी। मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सीधा आग्रह किया। उन्होंने कहा,

"यह कानून विपक्ष की मांग पर पेपर लीक रोकने के लिए लाया गया है, अब इस पर चर्चा करना आपकी जिम्मेदारी है।" रिजिजू ने बताया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य, खासकर युवा सांसद, बिल पर लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर रचनात्मक बहस में भाग लेने की अपील की। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेती ने भी विपक्ष से प्लेकार्ड हटाने और सार्थक चर्चा में शामिल ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो बड़े नीति सुधारों का अनावरण किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुध ारों का अनावरण किया है। इनका उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हुए कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। रक्षा मंत्री ने पिछले पांच दशकों में आईसीजी की असाधारण सेवा की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये दूरदर्शी नीतियां बल के मनोबल और प्रचालनगत क्षमता को और सुदृढ़ करेंगी, क्योंकि यह 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आईसीजी

को एक आधुनिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार समुद्री बल के रूप में मजबूत करने के संकल्प की पुष्टि की। पहली नीति निर्देश आईसीजी में अधिकारियों की भर्ती के लिए जेंडर–न्यूट्रल ढांचा लागू करके एक व्यापक, महिला–केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करती है। नीति की मुख्य विशेषताओं में महिला उम्मीदवारों को उनके पुरुष समकक्षों के समान अल्पकालिक सेवा नियुक्तियों (एसएसए) और स्थायी नियुक्तियों (पीए) में शामिल करना शामिल है। एसएसए का विकल्प पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी खोल दिया गया है। यह नीति प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण से ही कैरियर में प्रगति के समान अवसर सुनिश्चित करती है। विद्यमान महिला पीए अधिकारियों को भी पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। एसएसए पर कार्यरत वर्तमान महिला अधिकारियों को भी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन अपनी सेवा को पीए में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यह प्रगतिशील कदम नारी शक्ति और राष्ट्र के समुद्री सुरक्षा तंत्र में समान अवसर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एके-47 के कथित इस्तेमाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सिवान जिले में छात्र प्रदर्शन के दौरान एके–47 राइफल से गोलीबारी के आरोपों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। नयी दिल्ली, 28 जुलाई आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिहार के सिवान जिले में छात्र के प्रदर्शन के दौरान एके–47 राइफल से गोलीबारी के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा में

कथित अनियमितताओं के खिलाफ 25 जुलाई को सिवान में हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक कांस्टेबल द्वारा एके–47 राइफल का इस्तेमाल करने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद सोमवार को आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। दक्षिण– एशियाईऔर प्रवासी केजरीवाल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''आखिर भाजपा को क्या हो गया है? बिहार में हमारे छात्रों पर एक–47 से गोलियां चलाई गईं। क्या ये छात्र आतंकवादी हैं?'' उन्होंने कहा, ''मैं मोदी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी)–सम्राट(बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी) को याद दिलाना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार की ध ारती से नारा लगा था –सिंहासन खाली करो की जनता आती है।'' दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''कृपया छात्रों से पंगा न लें।'' सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने सोमवार को बताया कि वीडियो सामने आने के बाद जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) में तैनात कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है – राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान किया जाना ''लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न'' है। गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि प्रधान ''भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे।'' उन्होंने दावा किया कि इसी व्यवस्था ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। गांधी ने कहा कि प्रधान को इस्तीफा भी ''नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर'' देना पड़ा। उन्होंने कहा, ''और आज उसी व्यक्ति को संसद में भाजपा माला पहना रही है। यह कोई सम्मान नहींकृलाखों

बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''देश का हर छात्र यह देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरे को याद रखेगा।'' उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद सोमवार को जब पहली बार संसद पहुंचे तो भाजपा के कुछ सांसदों उनका स्वागत किया। बिहार के दरभंगा से लोकसभा सदस्य गोपालजी ठाकुर ने उन्हें 'पाग' (मिथिला की पारंपरिक टोपी) पहनाई।

पेयजल,पार्किंग,जाम,सीवर लाइन के नाम पर बड़े-बड़े गड्ढे व मूलभूत समस्याएं बनी राम नगरी की प्रमुख पहचान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। राम नगरी मे अश्वनीपुरम् कालोनी के अलावा कई कॉलोनियो,मोहल्लों मे पेयजल, पार्किंग,जाम,सीवर लाइन के नाम पर सड़कों पर खुदे गड्ढे,गंदगी सहित कई समस्याएं रामनगरी की प्रमुख पहचान बन चुकी हैं।जिसके चलते राम नगरी मे स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों तथा देश–विदेश से राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बारिश के दिनों में यहां पर और गंभीर समस्या बन रही है।देखा जाए तो इस समय राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रामनगरी आ रही है।जिसके चलते चार पहिया के वाहनों में बढ़ोतरी तो संभव ही है।वाहनों को खड़ा करने के लिए चाहे ट्रैफिक विभाग हो या फिर नगर निगम पर्याप्त संख्या में पार्किंग का भाव है जिसका पूरा–पूरा लाभ अवैध रूप से अयोध्या धाम में कुछ लोग उठा रहे हैं यह सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़े करने के नाम पर मुंह मांगा पैसे भी वसूल रहे हैं। इसके अलावा बीच–बीच में यातायात पुलिस अन्य संबंधित विभागों के साथ लोगो को जाम से राहत देने के लिए बैठक तो कल ली जाती है लेकिन वह बैठक इस कमरे तक ही सीमित रहती है और परिणाम आज भी यही है कि शहर के सभी मार्गो चौराहा पर जाम ही जाम दिखाई देता है।इस समय सबसे बड़ी समस्या शहर के अधिकतर मार्गो मोहल्ले व कॉलोनियों की गलियों मे सिविल लाइन बिछाने के लिए गड्ढे तो खुद दिए जाते हैं लेकिन उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है और आने वाले दिनों में खासकर बारिश के दौरान यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों के अलावा इध ार से गुजरने वाले लोगों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।इसी तरह कई समस्याएं रामनगरी में है परंतु इन गंभीर समस्याओं पर संबंधित विभाग चुप्पी साधे है जिसके चलते स्थानीय लोगों में उनके अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आक्रोश प्राप्त है।

पीडीपी अनुच्छेद-370 की बहाली की मांग को लेकर पांच अगस्त को करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन – महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर,, (एजेंसी)। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली और 'कश्मीर मुद्दे के समाधान' की मांग को लेकर पांच अगस्त को पूरे जम्मू–कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध ा प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की। उन्होंने कहा, ''यहां मौजूद हमारे सभी लोग पांच अगस्त को अपने–अपने जिलों में अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए शांतिपूर्ण विरोध ा–प्रदर्शन करेंगे।'' महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर–मंतर पर की गयी अपनी टिप्पणियों के लिए भी खेद जताया। शहरऔर स्थानीय मार्गदर्शिका केंद्र शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा अन्य लोगों ने पीडीपी अध्यक्ष की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन पर कश्मीरी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराने का आरोप लगाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''अगर कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर मेरे द्वारा की गई टिप्पणी से कोई आहत हुआ है, तो मैं माफी मांगती हूं।'' पीडीपी अध्यक्ष 23 जुलाई को जंतर–मंतर का दौरा किया और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी'(कॉजपा) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में हालात अलग हैं, क्योंकि वहां सुरक्षा बल उग्रवाद से लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की इन टिप्पणियों पर नेशनल कांफ्रेंस सहित विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, पीडीपी ने सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस पर आरोप लगाया कि उसने महबूबा के बयान को तोड़–मरोड़कर पेश करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का इस्तेमाल किया।

संपादकीय

सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही

मुमकिन है कि सरकार की नजर में कोई मांग नाजायज हो। फिर भी क्या यह लोकतांत्रिक तकाजा नहीं है कि वह संबंधित समूह से संवाद करे और तर्क–वितर्क से किसी सहमति पर पहुंचने का प्रयास करे?

दिल्ली के जंतर–मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन हटा कर अस्पताल में भर्ती करवाने की पुलिस कार्रवाई से फिर वही संदेश गया है कि वर्तमान सरकार के तहत अपनी शिकायत या मांग रखने की न्यूनतम गुंजाइश भी नहीं बची है। भूख हड़ताल का तरीका उचित है या नहीं अथवा वांगचुक एवं कॉकरोच जनता पार्टी की मांग कितनी उचित है, ऐसे प्रश्न फिलहाल पृष्ठभूमि में चले गए हैं। उनकी जगह इस बुनियादी सवाल ने ली है कि अपने को लोकतंत्र कहने वाली व्यवस्था में कोई समूह अपनी मांग रख रहा हो, तो उसके प्रति सरकार को क्या नजरिया अपनाना चाहिए? मुमकिन है कि सरकार की नजर में वो मांग जायज नहीं हो। फिर भी क्या यह लोकतांत्रिक तकाजा नहीं है कि वह संबंधित समूह से संवाद करे और तर्क–वितर्क से उसके साथ किसी सहमति पर पहुंचने का प्रयास करे? कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म व्यवस्था के शिकार नौजवानों के प्रति उच्च पदस्थ शख्सियतों की हेयदृष्टि का परिणाम है। विभिन्न स्तरों पर परीक्षा व्यवस्था में लगातार उजागर हुई गड़बड़ियों और कथित भ्रष्टाचार से ऊबे छात्र उसका मुख्य समर्थन आधार बने हैं। उनकी ही मांगों पर जोर डालने के लिए वांगचुक 23 दिन से अनशन पर बैठे हैं। इस दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने जंतर–मंतर पर इकट्ठा लोगों से संवाद की जरूरत नहीं समझी। अब चूंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और इसके पहले दिन वांगचुक और उनके साथियों ने संसद भवन की तरफ कूच करने का इरादा जताया था, तो सरकार ने अपना रुख और सख्त कर लिया है। मगर यह नजरिया लोकतंत्र में मौजूद हर उस सेफ्टी वॉल्व को बंद करता जा रहा है, जिनके जरिए असंतुष्ट समूहों का गुबार निकलते रहने से व्यवस्था स्थिर बनी रहती है। सरकार के लिए यह समझने का पहलू है कि बात ना करने या शिकायतों को नजरअंदाज करने से असंतोष का समाधान नहीं हो जाता। बल्कि उससे जन मानस में एक किस्म की टूटन होती है, जो व्यवस्था में उनके भरोसे को कम करती है। ष्कॉकरोचोंष् की बात ना सुनकर सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का शाश्वत सियासी संदेश

कमलेश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से कद्दावर ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को केवल भाजपा के एक व्यक्ति का इस्तीफा मानना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नवरत्नों में शुमार किये जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास भी उन्हें हासिल था। बावजूद इसके भारी जनदबाव के बीच यदि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो इसे कई स्तरों पर भाजपाध आरएसएस के राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी शासन सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं। देखा जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कर्नाटक मूल के भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया है, उसके निहितार्थ को भी समझे जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि यह सबकुछ अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ। थोड़ी नरमी सीजेपी के आंदोलनकारियों यथा– सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके ने दिखाई और थोड़ी भाजपा सरकार के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जैसे सिपहसालार ने। वास्तव में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में तीन बड़े संदेश देता हैकृजवाबदेही, जनदबाव की प्रभावशीलता और शिक्षा–युवा मुद्दों की बढ़ती राजनीतिक अहमियत। लेकिन इसके दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेंगे कि सरकार परीक्षा प्रणाली में कितने प्रभावी सुधार करती है और विपक्ष इस मुद्दे को कितनी देर तक राजनीतिक रूप से जीवित रख पाता है। सच कहूं तो 12 वर्षों में पहली बार केंद्र सरकार धर्मसंकट में फंसी थी, इसलिए उसने इंद्रप्रस्थ के इतिहास से सबक लेते हुए धृतराष्ट्र हठ का परित्याग किया और राष्ट्रवादी सूझबूझ प्रदर्शित किया। क्योंकि छात्र आंदोलन और जनदबाव को शांत करना, संसद और विपक्ष के साथ टकराव कम करना, शिक्षा मंत्रालय में नई शुरुआत का संदेश देना और सरकार की व्यापक राजनीतिक छवि को होने वाले नुकसान को सीमित करना, उसका तात्कालिक कर्तव्य समझा गया। जो एक हदतक सही भी है। जानकारों की मानें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलनों, विपक्ष के दबाव और परीक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवालों के बीच आया है। चूंकि अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कहा कि वे छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होने देना चाहते और स्थिति का दुरुपयोग न हो, इसलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि किसी बड़े जनदबाव के बाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो यह अनायास नहीं है, बल्कि भाजपा की सोची, समझी व गुनी हुई राजनीति है। इससे भाजपा सहित सभी दलों और सभी सामाजिक समूहों के नेताओं के लिए कुछ स्थायी सीख निकलती है और इसे सभी को समय रहते ही समझना होगा। पहला, सरकार की डैमेज कंट्रोल रणनीतिरू यदि सरकार को लगा कि विवाद पूरे शासन की छवि पर भारी पड़ रहा है, तो किसी एक मंत्री का इस्तीफा देकर व्यापक राजनीतिक नुकसान सीमित करने की कोशिश की जा सकती है। यह संसदीय और राजनीतिक दबाव कम करने की रणनीति भी हो सकती है। चूंकि जनता की अपेक्षाएँ किसी भी जातीय पहचान से बड़ी होती हैं। लिहाजा किसी नेता की जातीय पृष्ठभूमि से अधिक महत्व उसके कामकाज, जवाबदेही और परिणामों का होता है। इसलिए सरकार ने सही वक्त पर सटीक पोस्टमार्टम किया है और विभागीय कचरों तक की सफाई करवा डाली है। दूसरा, जवाबदेही का संदेशरू लगातार छात्र आंदोलनों और परीक्षा विवादों के बीच एक वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा यह संकेत देता है कि बड़े जनदबाव की स्थिति में सरकार राजनीतिक जवाबदेही दिखाने का विकल्प चुन सकती है। क्योंकि जवाबदेही स्वीकार करना कभी–कभी राजनीतिक नुकसान कम कर सकता है। वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर जिम्मेदारी लेना लंबे समय में पार्टी नेतृत्व का भरोसा बढ़ा सकता है।

युवाओं की राजनीतिक शक्ति का संकेतरू छात्र आंदोलनों ने यह साफ संदेश दिया कि रोजगार, परीक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दे अब राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इससे भविष्य में सरकारें इन विषयों पर अधिक सतर्क रह सकती हैं। चूंकि युवा मतदाता मुद्दा–आधारित राजनीति को महत्व देते हैं। इसलिए रोजगार, शिक्षा, परीक्षा की निष्पक्षता और अवसर जैसे विषय जातीय समीकरणों से ऊपर भी राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। युवा मतदाताओं को संदेश कि सरकार जल्द परीक्षा सुधार, पारदर्शिता और दोषियों पर कार्रवाई करती है। ऐसा करके उसने राजनीतिक नुकसान कम करने की पहल की है। क्योंकि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं होगा। सरकार ने जनदबाव को स्वीकार कियारू लंबे समय बाद किसी बड़े केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा सार्वजनिक दबाव के बाद हुआ है। इससे यह संदेश गया कि सरकार ने राजनीतिक नुकसान सीमित करने का रास्ता चुना। यदि विशेष रूप से भाजपा के ओबीसी नेताओं या सवर्ण नेताओं की बात करें, जो पार्टी की रीढ़ समझे जाते हैं, तो उन्हें यह समझाने का रणनीतिक प्रयत्न है कि किसी भी नेता को केवल अपनी सामाजिक पहचान पर नहीं, बल्कि सुशासन, संगठन क्षमता और जनविश्वास पर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बनानी चाहिए। अन्यथा देर सबेर हुई सार्वजनिक लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़तरू विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक जीत और जनदबाव की सफलता के रूप में प्रस्तुत करेगा, जबकि सत्तापक्ष इसे व्यवस्था सुधार और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में पेश करने का प्रयास करेगा। वाकई यह विपक्ष के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त है, क्योंकि विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा और भविष्य के आंदोलनों में इसे उदाहरण के रूप में पेश करेगा। सवाल है कि क्या यह विपक्ष के सामने घुटने टेकने की शुरुआत है? तो ऐसा निष्कर्ष अभी निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तभी कहा जा सकेगा जब सरकार भविष्य में भी हर बड़े आंदोलन पर इसी प्रकार झुके, या अन्य विवादों में भी लगातार इस्तीफे और नीतिगत बदलाव दबाव में करने पड़े। भाजपा के लिए आंतरिक संदेशरू चूंकि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इसलिए आसन्न संकट आने पर केवल राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि प्रशासनिक समाधान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लिहाजा यह संकेत भी माना जा सकता है कि संगठन और सरकार, दोनों स्तरों पर प्रदर्शन और सार्वजनिक धारणा का महत्व बढ़ गया है। वस्तुतः भाजपा इसे जवाबदेही के संदेश में बदलने की कोशिश करेगी। इसलिए सरकार यह तर्क दे सकती है ।

सोनम वांगचुक का अनशन और शिक्षा सुधार का एजेंडा

अरुण

डनायक भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकताय इसके लिए नवाचार, जवाबदेही और उद्यमशीलता को जोड़ना होगा। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा जनसंख्या है, जो तभी लाभकारी बनेगी जब उसे गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालय के सरकारी या निजी होने से नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों, प्रभावी प्रबंधन और जवाबदेही से तय होती है। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने 24 जून को गुरुग्राम में केंद्र सरकार के दो मंत्रियों जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से लिखित आश्वासन मिलने के बाद 26 दिन लंबा अनशन समाप्त किया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और लंबे समय से जारी छात्र आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया। सरकार ने वादा किया कि जंतर–मंतर और संसद मार्च में शामिल छात्रों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा तथा नीट प्रश्नपत्र लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही संसद में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के कदम उठाने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो इंस्टाग्राम वीडियो संदेशों में फास्ट–ट्रैक अदालतों और कठोर दंड वाले विधेयक का प्रारूप तैयार होने की बात कही, हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन लगातार बैठकों और बढ़ते युवा प्रतिरोध के दबाव में अंततरू 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में उपवास केवल राजनीतिक दबाव का साधन नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि, नैतिक जागरण और संवाद की प्रेरणा भी था। उन्होंने अपने आंदोलनों में कभी संवाद और समझौते के द्वार बंद नहीं किएय सप्रू और जयकर जैसे मध्यस्थों ने कई अवसरों पर समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। इसी परंपरा में सोनम वांगचुक के अनशन और छात्र आंदोलन की समाप्ति को किसी पक्ष की हार–जीत नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहमति और जवाबदेही की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए।जंतर–मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन तेजी से कई राज्यों में फैल गया और उनकी मांगें नीट प्रश्नपत्र लीक से आगे बढ़कर पूरी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तक पहुंच गई। छात्रों का कहना है कि केवल नए कानून पर्याप्त नहीं होंगेय संस्थागत कमजोरियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर ध्यान देना होगा। बार–बार होने वाले प्रश्नपत्र लीक ने उनकी मेहनत और भविष्य को असुरक्षित बना दिया है, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए छात्र सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती असमानता पर चिंतित हैं। पुलिस बल प्रयोग से घायल होने के बावजूद छात्रों ने आंदोलन जारी रखा, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक परीक्षा का न्याय नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। छात्रों ने सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली, सीयूईटी में देरी, परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरियों को भी गंभीर समस्याएं बताया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम चुनाव, संसदीय उत्तरदायित्व और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रीस्तरीय दायित्व तय करना भी है। सरकार ने अंततरू शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर एक कदम उठाया, हालांकि इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का स्पष्ट स्वीकार नहीं दिखता। उच्च शिक्षा विभाग में सचिव स्तर पर फेरबदल और एनटीए के संविदा कर्मियों को हटाना छात्र संगठनों के अनुसार उनकी मूल मांगों का समाधान नहीं है।विपक्ष ने प्रधानमंत्री के संदेश को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक चर्चा का दबाव बनाया। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि विपक्ष की सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति सफल रही। अब जब छात्र अपने घर लौट चुके हैं, संसद के सुचारू रूप से चलने और शिक्षा सुधार जैसे दीर्घकालिक विषयों पर राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनने की संभावना है।फिल्म जगत, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज के व्यापक समर्थन ने इस आंदोलन को छात्रों के दायरे से निकालकर शिक्षा सुधार और लोकतांत्रिक जवाबदेही का व्यापक सामाजिक अभियान बना दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल सरकार पर निर्भर नहीं हो सकताय इसके लिए नवाचार, जवाबदेही और उद्यमशीलता को जोड़ना होगा। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा जनसंख्या है, जो तभी लाभकारी बनेगी जब उसे गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले। शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालय के सरकारी या निजी होने से नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों, प्रभावी प्रबंधन और जवाबदेही से तय होती है। भवन, स्मार्ट क्लास या डिजिटल उपकरण पर्याप्त नहीं हैंय असली सुधार अच्छे शिक्षण, नियमित मूल्यांकन और शिक्षकों की जिम्मेदारी से आता है।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन – अस्तित्व पर मंडराता खतरा

ललित

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े–बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया। जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ–साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों–ड्रिप और स्प्रिंकलर–को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन–आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है।

मोदीजी की बड़ी हार लेकिन नरेटिव की लड़ाई में कांग्रेस को मेहनत करना होगी

शकील

कांकरोच जनता पार्टी ने अपना आन्दोलन खत्म कर दिया मगर राहुल की लड़ाई लंबी है। जो लोग कहते थे कि राहुल जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाते उसका जवाब यही है। राहुल अमित शाह और मोदी से सवाल कर रहे हैं। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शनिवार को उन्होंने कहा कि वह तो होना ही था मगर सवाल पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। सरकारी एजेंसियां अब खेल नरेटिव का है। प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी फेक इमेज अब नहीं बन सकती। बीजेपी आरएसएस को उसमें रूचि भी नहीं है। लेकिन हां, राहुल की छवि खराब करने का काम और तेज होगा।भाजपा संघ की राजनीति ही यही है। दूसरे की लकीर छोटी करना। और यहीं कांग्रेस को बहुत होशियारी से काम करने की जरूरत है। मोदी की 12 साल में यह सबसे बड़ी हार है। उनके भक्त, गोदी मीडिया खुद पार्टी के लोग और आरएसएस सब सोचते थे कि मोदी कोई जादू मारेंगे और जंतर मंतर खाली हो जाएगा। मास्टर स्ट्रोक। मोदी का चौंकाने वाला फैसला। इसी तरह यह लोग मोदी की फेक इमेज बनाते थे। गुजरात के झूठे विकास माडल से लेकर, छप्पन इंच की छाती और मोदी नहीं तो कौन जैसी झूठी धारणाएं बनाकर वे मोदीजी की महिमा मंडन करते थे।लेकिन जानते थे यह सच नहीं है। इसलिए दूसरी तरफ राहुल की छवि खराब करने का काम भी मोदी की छवि बनाने जैसी मेहनत से करते थे। खुद राहुल ने कहा कि– मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों–करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए छुपाई नहीं जा सकती। अब धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के साथ मोदी की सारी इमेजें एक साथ टूट गईं। हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते एक बड़ा दावा था। और यह भी यूपीए सरकार को कमजोर दिखाने के लिए कि वहां मंत्री हटा दिए जाते थे।यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह अच्छा करते थे कि किसी पर आरोप होने के बाद उसका मंत्री पद छीन लेते थे। लेकिन यहां तो दबंगी में कहा जाता था कि यह यूपीए सरकार नहीं है भैया! यह एनडीए है यहां इस्तीफे नहीं होते। फिर क्या हुआ? शेन–जेड ने बता दिया कि सत्य और अहिंसा की ताकत क्या होती है। इस नई पीढ़ी के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। समय के अनुसार इसकी वैल्यूश नई हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। गांधी जी का सत्य, अहिंसा उनमें सबसे ऊपर है। भारत से दुनिया में जाकर सार्वभौमिक सिद्धांत बना। जेन–जेड भी इस पर कायम रहा। गांधीजी की प्रासंगिकता जिसे यही लोग चौलेंज करते रहते थे फिर प्रतिपादित हुई। भारत के तीनों बड़े नायक जंतर मंतर पर लगातार छाए रहे।गांधी, भगत सिंह और डा. आम्बेडकर। भाजपा संघ का कोई नायक वहां नहीं था। उल्टा मोदी को इन करीब 36–37 दिनों में वहां सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनके सारे आवरण वहां उतर गए। कहां अपनी ही पार्टी में सबसे बड़ा कद होने की धारणा बनाने के लिए वाजपेयी, आडवानी और मुरली मनोहर जोशी का नाम लेना भी गुनाह बना दिया गया था। और बाहर तो सीधा नेहरू से मुकाबला किया जाता था। एक्जिक्यूटिव ब्रांच मगर 12 साल की सारी मेहनत सवा महीने में धुल गई। सच के सामने। छात्रों का आन्दोलन सच के मुद्दे पर था। बहुत लंबे समय तक शिक्षा जिसमें पेपर लीक सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षाएं ठीक से न करा पाने, बेरोजगारी जैसे छात्र और युवाओं के भविष्य से जुड़े जरूरी मुद्दे थे दबे रहे। मगर जैसा कि कहते हैं कि हर चीज का समय आता है तो वह आया। ब्लेम सारा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर आया। फंस गए। उन्होंने तो जैसा सब बोल रहे थे बिना किसी जवाबदेही के ऐसे ही बोल दिया था। बेरोजगार युवाओं को काकरोच। और युवा एवं छात्रों को बात लग गई। काकरोच जनता पार्टी बन गई। और दिल्ली के जंतर मंतर से जो आन्दोलन शुरू हुआ वह ऐसा फैला कि देश भर से होता हुआ विदेशों तक फैल गया। पहले तो किसान, मजदूर या नोटबंदी जीएसटी के समय छोटे व्यापारियों के विरोध पर जैसी गालियां उन्हें दिलवाईं गईं थी वैसी ही छात्रों को दिलवाई गईं। मगर यह जेन–जेड था। 25 साल से कम उम्र। सुबह के हवा के झोंके की तरह ताजगी से भरा हुआ। उस पर इन पुराने हरबों का कोई असर नहीं होता है। उसकी भाषा नई, विचार नए और साहस से भरपूर।मोदी जी ने सोचा उनके प्लेटफार्म से जाकर बात करूं। दो दिन इंस्टाग्राम पर गए। मगर उल्टा मजाक बन गया। जेन–जेड में तमाशे नहीं चलते। दिल के सच्चे हैं तो सच को फौरन पहचान लेते हैं। मोदी की हिम्पोक्रेसी मित्रों नफरत और विभाजन के नशे में डूबो दिए गए लोगों तक तो चल गई मगर डियर फ्रेन्ड्स छात्रों और युवाओं पर नहीं चला। यहां तो हिन्दू–मुसलमान, जात–पात, स्त्री–पुरुष कोई भेद था ही नहीं। पूरे देश ने देखा कि लड़कियां यहां सबसे सहज और निर्भय दिखीं। तो यह नई पीढ़ी की नई दुनिया थी। मोदी जी के पुराने बांटो, डराओ के तरीकों का

इन पर कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी इस पीढ़ी को समझ ही नहीं पाए। लेकिन यह छात्र और नौजवान मोदीजी को अच्छी तरह समझ गए। उनका मजाक उड़ाने के अलावा उनके बारे में कुछ और सोचा ही नहीं। सरकारी एजेंसियां दूसरी ओर राहुल की तरफ अपने आप खींचे चले गए। जंतर मंतर पर सबसे लंबी 23 दिन की भूख हड़ताल करने वाली जेएनयू की छात्रा नेहा बोरा अपने साथियों के साथ राहुल गांधी के यहां 10 जनपथ पहुंच गईं। नेहा जंतर मंतर की सबसे बड़ी स्टार बन और आरएसएस के हाथ में सौंप दिया गया है? इस पर उनका गहन अध्ययन था। और उन्होंने 10 जनपथ पर राहुल के साथ प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि शिक्षा के बारे में हमारी सबसे अच्छी बातचीत राहुल जी के साथ हुई। मतलब राहुल की जो शिक्षा की समझ है वह आज की युवा पीढ़ी की तरह है। उससे मेल खाती है। अखबार राहुल इस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े रहे। जबकि पेपर लीक और सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ उनका आंदोलन पहले से चल रहा था।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई पर जन–जागरूकता संदेश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाना तथा इसके बचाव, समय पर जांच और उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वायरल हेपेटाइटिस यकृत (लीवर) की सूजन संबंधी बीमारी है, जो मुख्यतः वायरस के संक्रमण से होती है। समय पर पहचान और उचित उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इस अवसर पर आयोजित जन–जागरूकता कार्यक्रम में हेपेटाइटिस के विभिन्न प्रकारों, उनके लक्षणों, बचाव के उपायों तथा समय पर जांच एवं उपचार के महत्व की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि हेपेटाइटिस ए एवं ई मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमित रक्त, असुरक्षित सुई, असुरक्षित यौन संबंध तथा संक्रमित माँ से शिशु में फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस डी केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्तियों में होता है। विशेषज्ञों ने बताया कि बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट दर्द, आंखों एवं त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), गहरे रंग का मूत्र तथा अत्यधिक थकान इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेकर जांच एवं उपचार कराना आवश्यक है। जनसामान्य से अपील की गई कि वे स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें, भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, हेपेटाइटिस–बी का टीकाकरण अवश्य कराएं, केवल डिस्पोजेबल या स्टरलाइज्ड सुई एवं सिरिंज का ही प्रयोग करें, रक्त चढ़ाने से पहले जांचा हुआ सुरक्षित रक्त ही लें तथा रेजर, नेलकटर एवं टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं साझा न करें। सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाने और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर भी विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम और उपचार संभव है। समय पर जांच, टीकाकरण, स्वच्छता और जन–जागरूकता के माध्यम से इसके संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। सभी नागरिकों से "हेपेटाइटिस मुक्त समाज" के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया। इस अवसर पर डॉ. संतोष जायसवाल, नोडल अधिकारी, वायरल हेपेटाइटिस कार्यक्रम एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर, डॉ. जियाउल हक, एपिडेमियोलॉजिस्ट, डीसीपीएम मो. खुबैब रजा, ब्लॉक स्तर के प्रतिभागी चिकित्सा अधिकारी, ए.आर.ओ., एच.ई.ओ. तथा अन्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मेडिकल कॉलेज जौनपुर में लैप्रोस्कोपी से पहली सफल सर्जरी, 17 वर्षीय युवती का हुआ पित्त की पथरी का ऑपरेशन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में पहली बार लैप्रोस्कोपी (दूरबीन) विधि से पित्त की पथरी का सफल ऑपरेशन किया गया। इस उपलब्धि के साथ मेडिकल कॉलेज ने आधुनिक शल्य चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) आर.बी. कमल के निर्देशन में जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) ए.ए. जाफरी एवं उनकी टीम ने खेतासराय निवासी 17 वर्षीय युवती की लैप्रोस्कोपी विधि से सफल सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति पूरी तरह सामान्य है और वह चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। इस सफल सर्जरी में डॉ. इमरान, डॉ. नाजिया, डॉ. धनंजय, डॉ. राजन्य प्रजापति, डॉ. अली हैदर तथा नर्सिंग अधिकारी

अनुज सहित अन्य सहायक कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद पटेल और सीनियर रेजिडेंट डॉ. दत्ता रेड्डी ने मरीज को सुरक्षित एनेस्थीसिया प्रदान कर ऑपरेशन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) आर.बी. कमल ने शल्य चिकित्सा एवं एनेस्थीसिया विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, ताकि जनपद और आसपास के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी संस्थान में इसी प्रकार की उन्नत एवं जटिल शल्य चिकित्सा सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।

किसानों को एक ही छत के नीचे मिलेंगे समस्त कृषि निवेश एवं उचित परामर्श

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सिद्धिकपुर में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्रीजंक्शन) योजना के तहत चयनित 21 अभ्यर्थियों की 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। समापन समारोह में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उप कृषि निदेशक डा. अश्वनी कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को समस्त कृषि निवेशों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जैव उत्पाद, कृषि यंत्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, इन केंद्रों पर किसान आधुनिक तकनीक, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का सुझाव, फसल प्रबंधन और बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इसके अलावा छोटे कृषि यंत्र किराए पर मिलेंगे, उपकरणों की मरम्मत, कृषि उत्पादों की बिक्री और प्रसंस्करण की सुविधा भी मिलेगी। उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि प्रत्येक वन स्टाप शॉप (एग्रीजंक्शन) केंद्र की लागत लगभग 4.22 लाख रुपया निर्धारित की गई है, जिसमें 3.5 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पहले वर्ष में किराया सहायता के रूप में 24 हजार रुपए और प्रशिक्षण व अन्य खर्चो के लिए भी सहायता दी जाएगी। प्रति केंद्र 77900 तक की सहायता का प्रावधान है, उन्होंने कहा कि किसानों को उनके क्षेत्र में समय से कृषि निवेशों की उपलब्धता से जहा उत्पादन बढ़ेगा वही रोजगार का सृजन भी होगा। आरसेटी निदेशक उपेंद्र कुमार ने कहा कि योजना से किसानों को जहां एक ही जगह कृषि निवेश प्राप्त होगे वही उचित परामर्श भी मिलने से लागत कम एवं उत्पादन अधिक प्राप्त होगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अंत में अभिषेक दुबे वरिष्ठ संकाय द्वारा आभार ज्ञापित किया गया। इस मौके पर कार्यालय सहायक जगदीश गौड़ सहित 21 प्रशिक्षु अभ्यर्थी मौजूद रहे।

रानी लक्ष्मीबाई मार्ग उद्योग व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

लखनऊ, (संवाददाता)। राजाजीपुरम परिक्षेत्र उद्योग व्यापार मंडल की इकाई रानी लक्ष्मीबाई मार्ग उद्योग व्यापार मंडल (सम्बद्ध लखनऊ व्यापार मंडल) की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को उत्साह और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में नई टीम ने व्यापारियों के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और व्यापारी एकता को सशक्त करने का संकल्प लिया।समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी रहे, जबकि अध्यक्षता उमेश कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने तथा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव सक्रिय रहने का आह्वान किया।नई कार्यकारिणी में सोनू घई को अध्यक्ष, जीत सिंह को महामंत्री, अंकुर मेहता को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा हिमांशु तिवारी, सर्वेश शर्मा, रशीद अहमद, एम.के. अग्रवाल, बीनू गुप्ता और संजीव शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मो. शरीफ इब्राहिम, अंकित, मदन कुमार, जुबेर अंसारी तथा रजा ईमामध्वीरेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष, जगदीश कुमार, गोदी गुप्ता और सुनील कुमार शर्मा को मंत्री तथा श्याम सुंदर को विधि सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई गई।मुख्य अतिथि आनंद द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारियों का संगठित रहना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत व्यापार मंडल ही व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से शासन और प्रशासन के समक्ष रखकर उनका समाधान करा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि किसी भी संगठन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकजुटता और सक्रिय कार्यशैली होती है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से समन्वय, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक व्यापारी को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया।

नकली दवाओं की बिक्री, फर्जी बिल और जीएसटी चोरी मामले में पांच पर मुकदमा

लखनऊ, (संवाददाता)। एफएसडीए के औषधि निरीक्षक की तहरीर पर नकली दवाओं की बिक्री, फर्जी बिल बनाने और जीएसटी चोरी के आरोप में कैसरबाग थाने में पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई रद्द हो चुके औषधि लाइसेंस के इस्तेमाल और डिजिटल रिकॉर्ड हटाने के मामले में की गई है। जांच में नामी कंपनियों की नकली दवाएं बेचने और फर्जी इनवॉइस जारी करने का खुलासा हुआ है। सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश यादव ने बताया कि जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड ने शिव शक्ति मेडिकल से संदिग्ध दवाओं की आपूर्ति की शिकायत की थी। जांच के दौरान 10 सितंबर 2025 को दुकान बंद मिली थी। गंभीर अनियमितताओं के कारण 5 जनवरी 2026 को फर्म का औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद, फर्म के नाम से दवाओं की खरीद–बिक्री जारी रही। जुलाई में गाजियाबाद की एक दवा फर्म से ग्लेनमार्क कंपनी की टेल्मा–एएम और टेल्मा–एच ब्रांड की संदिग्ध दवाएं बरामद हुईं। इनकी बिक्री शिव शक्ति मेडिकल के नाम से जारी फर्जी इनवॉइस के जरिये सामने आई। मुख्य आरोपी कपिल जायसवाल ने स्वीकार किया कि उसका रद्द लाइसेंस, जीएसटी नंबर और मार्ग सॉफ्टवेयर की आईडी–पासवर्ड कर्ज के बदले दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। उसे इसके एवज में तीन से आठ फीसदी तक नकद कमीशन मिलता था। औषधि विभाग ने कपिल जायसवाल (शिव शक्ति मेडिकल) को मुख्य आरोपी बनाया है। हरमीत सिंह (मीत एंटरप्राइजेज), प्रियांशु पाल (विद्या फार्म), साहिल जैदी (आरएन फार्मा) और आबिद अली अतहर भी आरोपी हैं। एफएसडीआई ने विद्या फार्म के लैपटॉप को कब्जे में लेकर जांच कराई। इसमें टेल्मा दवाओं के रिकॉर्ड मिले और उनकी बैच हिस्ट्री डिलीट करने के साक्ष्य भी सामने आए।

जहां मंत्री ने लगाया था पौधा, वहां अब निशान तक नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से एक जिला–एक नदीश योजना शुरू की है। इस योजना में सीतापुर की सरायन नदी भी शामिल है। इस नदी के जीर्णोद्धार समिति के सदस्य और बीबीएयू के प्रो. वेंकटेश दत्ता के रेस्टोरेशन प्लान के तहत पिछले साल कैंची पुल के नीचे विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 को पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। सरायन नदी के किनारे पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। तब सीतापुर वन प्रभाग ने एक विशेष पौधरोपण अभियान व प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त थीम के तहत सरायन नदी का सफाई अभियान चलाया। इसमें नगर पालिका परिषद सीतापुर, जिला गंगा समिति, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग व स्वयंसेवी संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उस समय के जिलाधिकारी ने सरायन की सफाई और नगर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प दिलाया था। इस अभियान का उद्देश्य नदी के सौंदर्य में वृद्धि करना और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र जीवित करना। जिससे भूमि कटाव को रोका जा सके और नदी के जल स्तर को बनाए रखने में भी मदद मिले। ठीक एक साल एक महीने बाद जब हम कैंची पुल के नीचे पौधारोपण वाली जगह पर पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। वहां एक भी पौधा तो दूर उसके अवशेष भी देखने को नहीं मिले। लगा ही नहीं कि यहां कभी पौधरोपण भी हुआ था। वहीं सीवर का गंदा पानी नदी में गिर रहा था। पास ही लोग नदी किनारे शौच के लिए जा रहे थे। यह हाल तो शहर के बीचोबीच का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जगह क्या स्थिति होगी। पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष आशीष मिश्र कहते हैं कि नदी शासकीय और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। बदहाली का प्रमुख कारण कब्जा, चीनी मिलों और फैक्टरियों का केमिकल युक्त पानी। शहर में एक भी एसटीपी नहीं है। शहर में लाखों पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना था।

नई एसआईटी निकाल सकती है कुछ नए साक्ष्य, बदल जाएगी मंदिर में दर्शन व्यवस्था

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गठित नई एसआईटी जांच की परत–दर–परत समीक्षा करेगी। डीआईजी और एसएसपी के जुड़ने से सुपरविज मजबूत होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही नई एसआईटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। दान पेटिकाओं से चोरी के मामले में रामजन्मभूमि थाने में रिपोर्ट दर्ज है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी इस मामले की विवेचना कर रहे हैं। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले सुनवाई हुई थी, जिसमें न्यायाधीश ने आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए नई कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। नई एसआईटी के इंतजार में मामले की पुलिस जांच धीमी पड़ गई थी। शनिवार को ही सरकार ने नई एसआईटी गठित की है। इसमें लखनऊ के आईजी किरण एस के साथ ही अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को भी शामिल किया गया है। अब टीम के गठन के बाद लंबित बिंदुओं पर तेजी से

कार्रवाई होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी सबसे पहले अब तक की केस डायरी, धारा 161 बीएनएसएस के तहत दर्ज बयान, पुलिस रिमांड के दौरान प्राप्त तथ्यों, जब्ती मेमो, बरामदगी, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान करेगी। यदि किसी कड़ी में कमी या विरोधाभास मिलता है तो संबंधित गवाहों और आरोपियों से दोबारा पूछताछ की जा सकती है। वहीं, डीआईजी के जुड़ने से विवेचना की सुपरविजन नोट के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा होगी। जबकि एसएसपी के होने से सर्विलांस, साइबर सेल, तकनीकी प्रकोष्ठ और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय रहेगा। इससे तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परस्पर मिलान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी यह भी देखेगी कि अब तक जुटाए गए साक्ष्य न्यायालय में अभियोजन की कसौटी पर कितने मजबूत हैं। यदि किसी बिंदु पर साक्ष्य की शृंखला कमजोर पाई जाती है तो उसे मजबूत करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, डिजिटल डेटा या विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। वहीं, डीआईजी सोमेन बर्मा ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।

शिविर में जांची गईं 65 वरिष्ठ नागरिकों की आंखें

लखनऊ, (संवाददाता)। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के आपका विधायक, आपके द्वार अभियान का 176वां सप्ताह रविवार को आयोजित हुआ। इस दौरान अर्जुनगंज मंडल के मेड़ईखेड़ा में जनसुनवाई शिविर लगा, जिसमें 15 जनसमस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। 65 वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की निशुल्क जांच की गई। बॉयज और गर्ल्स यूथ क्लब का गठन भी हुआ। क्लबों को क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और कैरम किट प्रदान की गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावियों को साइकिलें देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि शिक्षा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग देना प्राथमिकता है। बताया कि शिविर में मुख्यमंत्री राहत कोष सहायता, मंदिरों के सुंदरीकरण, विधवा पेंशन और सड़क निर्माण सहित 15 आवेदन प्राप्त हुए। डॉ. राजेश्वर सिंह ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

संक्षिप्त खबरें

नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। सरोजनीनगर थाना पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग से कथित दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और पाक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने स्वयं को अविवाहित बताकर नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। साथ ही ब्लैकमेल कर पीड़िता से गहने भी ले लिए।पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता ने सरोजनीनगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को अभिषेक सिंह उर्फ गोलू निवासी अमौसी बहला–फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि आरोपी पहले से विवाहित होने के बावजूद स्वयं को अविवाहित बताता रहा और इसी झांसे में लेकर उसने नाबालिग का वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कथित रूप से कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करते हुए गहने भी ले लिए।तहरीर के आधार पर सरोजनीनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई।जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद है।

बीबीएयू और सीबीएलयू के बीच एमओयू, शिक्षा, शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ और चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय (सीबीएलयू), भिवानी के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्चुअल माध्यम से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध, नवाचार, कौशल विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे।एमओयू हस्ताक्षर समारोह में बीबीएयू के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल तथा सीबीएलयू की कुलपति प्रो. दीप्ति धर्माणी मौजूद रहीं। समझौते पर बीबीएयू के कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह और सीबीएलयू की कुलसचिव प्रो. भावना शर्मा ने हस्ताक्षर किए।समझौते के तहत शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमआरसी), लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (एमओओसी) के माध्यम से ऑनलाइन व्याख्यानों और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास, उद्यमिता, नवाचार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में भी दोनों संस्थान सहयोग करेंगे।दोनों विश्वविद्यालय आपसी सहमति से शैक्षणिक संसाधनों का आदान–प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालयों ने स्पष्ट किया कि इस सहयोग के कारण किसी भी संस्थान पर कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं आएगा। समारोह में बीबीएयू की ओर से प्रो. राम चंद्रा, प्रो. शिल्पी वर्मा, प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा, प्रो. सुभाष मिश्रा, प्रो. धीरेंद्र पांडेय और डॉ. सुदर्शन चक्रधारी उपस्थित रहे।

संविधान दिवस पर लखनऊ में एक लाख लोगों की रैली करेगी आरपीआई

लखनऊ, (संवाददाता)। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. रामदास आठवले ने रविवार को लखनऊ में आयोजित प्रेसवार्ता में बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर वृंदावन स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में पार्टी की विशाल रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह उत्तर प्रदेश में आरपीआई की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें करीब एक लाख कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे।डॉ. आठवले ने कहा कि रैली में प्रदेश के प्रत्येक जिले से 500 से 1000 कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 13 सितंबर को मुरादाबाद, 25 सितंबर को आगरा तथा जल्द ही आजमगढ़ में भी जनसभा आयोजित की जाएगी।उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश को मजबूत संविधान दिया, जिसकी बदौलत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का अधिकार मिला। उन्होंने संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आरपीआई की प्रतिबद्धता दोहराई।आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर डॉ. आठवले ने कहा कि आरपीआई ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से 4 से 5 विधानसभा सीटों की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष और सुनील बंसल से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली तो आरपीआई 20 से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर विचार करेगी।

अमौसी एयरपोर्ट पर बम की झूठी सूचना से मचा हड़कंप

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (अमौसी) एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी सूचना देकर सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचाने वाले एक व्यक्ति को सरोजनीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने शराब के नशे में डायल–112 पर फोन कर एयरपोर्ट पर बम होने की भ्रामक सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में सरोजनीनगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 की रात करीब 11रू45 बजे डायल–112 पर एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने अमौसी एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। एयरपोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर संदिग्ध स्थान की गहन जांच की गई, लेकिन काफी देर तक चली सघन तलाशी के बाद भी कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।जांच में सूचना पूरी तरह झूठी और भ्रामक पाए जाने पर सरोजनीनगर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान शुरू की।विवेचना के दौरान कॉलर की पहचान श्याम सुंदर (35 वर्ष) पुत्र राज किशोर, निवासी ग्राम जयसिंहपुर, थाना बिधनू, जनपद कानपुर के रूप में हुई।

विदेशी शासनकाल में आयुर्वेद के संरक्षण के संकल्प से हुआ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का गठन'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी कार्यालय में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में संगठन की सदस्यता अभियान को गति देने तथा भारत सरकार की मंशा के अनुरूप भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन एवं जनस्वास्थ्य में उसकी अग्रणी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष डॉ विजय जौहरी ने कहा कि आयुर्वेद भारत की हजारों वर्ष पुरानी वैज्ञानिक एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जिसने सदियों तक जनस्वास्थ्य की रक्षा की। उन्होंने कहा कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में विदेशी शासनकाल के दौरान आयुर्वेद की शिक्षा, चिकित्सा एवं औषध निर्माण व्यवस्था उपेक्षित होती चली गई। आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों, चिकित्सकों के पंजीकरण तथा औषध निर्माण की कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में देशभर के आयुर्वेदाचार्यों एवं वैद्यों ने यह अनुभव किया कि यदि आयुर्वेद को संगठित नहीं किया गया तो भारत की यह महान चिकित्सा परंपरा कमजोर होती जाएगी। डॉ विजय जौहरी ने कहा कि वर्ष 1970 में संसद द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का गठन हुआ। इस ऐतिहासिक अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार करने और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे आयुर्वेद शिक्षा के राष्ट्रीय मानक निर्धारित हुए तथा चिकित्सकों के पंजीकरण एवं शिक्षा व्यवस्था को विधिक आधार प्राप्त हुआ। इन सतत प्रयासों के फलस्वरूप आज देश में बीएएमएस, एमडी, एमएस, पीएचडी सहित उच्च आयुर्वेद शिक्षा तथा अनुसंधान की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। डॉ विजय जौहरी ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन सदैव भारत सरकार एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य नीतियों का सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा जनस्वास्थ्य संरक्षण के लिए संचालित सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जन–जागरूकता अभियानों, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, टीकाकरण, आपदा राहत, स्वास्थ्य शिविरों तथा अन्य लोकहितकारी गतिविधियों में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के आयुर्वेदिक चिकित्सक सक्रिय एवं सहयोगी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी चिकित्सकों से आह्वान किया कि वे शासन–प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ, निरोग एवं सशक्त भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम में विर्गो यू ए पी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के राजीव शर्मा एवं आयुर्वेदिक स्टोर सिंह एजेंसी के प्रोप्राइटर सरदार सर्वजीत सिंह ने आयुर्वेदिक प्रचार सामग्री वितरित कर सभी का आभार प्रकट किया इस अवसर पर डॉ एस पी कौशल डॉ मुकेश कुमार प्रभारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर डॉ हेमेंद्र वर्मा, डॉ आर पी सक्सेना, डॉ अविनाव श्रीवास्तव, डॉ सुमन अग्रवाल, डॉ पल्लवी सक्सेना, डॉ रचना रस्तोगी, डॉ सूफिया, डॉ रजत सक्सेना, डॉ अभिनव सक्सेना, डॉ अतुल जौहरी, डॉ रवि सक्सेना, डॉ राजीव वर्मा, डॉ मुजीब, डॉ राजेंद्र कुशवाहा, सहित काफी संख्या में चिकिसको ने अपनी सहभागिता की।

5 दिवसीय मण्डल स्तरीय किशोरावस्था शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जेडी की अध्यक्षता में शुरु

अयोध्या। पांच दिवसीय मण्डल स्तरीय किशोरावस्था शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुरु हुआ। जो 31 अगस्त तक चलेगी।कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने किशोरावस्था शिक्षा के विभिन्न विषय वस्तुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक अपने जनपद के विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षा को पूरे मन से पढ़ाये। कार्यक्रम मे विषय विशेषज्ञ प्रतिभा तिवारी प्रवक्ता डायट, डॉ जगजीत कुमार मंडलीय मनोविज्ञान शाला, डॉ अरूणेश कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती अलका सोनी मंडलीय मास्टर ट्रेनर के द्वारा

किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न विषय वस्तुओं पर परिचर्चा एवं गतिविधियां कराई जा रही हैं।निशा मिश्रा सह नोडल अधिकारी, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम ने बताया कि अयोध्या मण्डल में प्रत्येक जनपद से पांच शिक्षक, कुल 25 शिक्षकों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।डॉ अन्नपूर्णा सिंह कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में योगदान दे रही हैं।अलक्ष्या पाण्डेय, छाया देवी, कनक चतुर्वेदी,सहित कई लोग उपस्थित रहे।

बारिश से बड़ा रमना क्षेत्र में जलभराव, कई शिकायतों के बावजूद नहीं हुई सुनवाई का आरोप

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। शहर के बड़ा रमना क्षेत्र स्थित नानकपुरा वार्ड में बारिश के बाद जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश होते ही मोहल्ले की सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है।मोहल्ला वासियों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए वे कई बार नगर निगम और क्षेत्रीय विधायक को प्रार्थना–पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि बार–बार शिकायत करने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं सुधारी गई, जिससे हर बारिश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जलभराव के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत होती है।साथ ही गंदा पानी जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।इस समस्या पर मोहल्ले वासियों ने नगर निगम प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से जल्द से जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की है,ताकि आगामी बारिश में लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।

सावन मेला व कांवड़ यात्रा को लेकर फायर विभाग अलर्ट – एमपी सिंह

अयोध्या। सावन मेला एवं कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में सावन मेले व कावड़िये व श्रद्धालु अयोध्या आते है।इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए कमिश्नर राजेश कुमार डीआईजी सोमेन वर्मा डीएम शशांक त्रिपाठी एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं।वही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।यह जानकारी देते हुए प्रभारी उपनिदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/अयोध्या एमपी सिंह ने बताया कि सावन झूला 15 अगस्त

से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त को खत्म होगा।सावन मेला और कावड़ और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक है।बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख स्थलों पर टेंट,मेला आयोजकों, मंदिर समितियों से अपील करते हुए कहा कि सभी अस्थायी टेंट अग्निशमन सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही लगाए जाएं।टेंट में खुले या लटकते बिजली के तारों का प्रयोग न करें तथा घटिया या ओवरलोड विद्युत उपकरणों से बचें।उन्होंने कहा कि टेंट की संरचना में लोहे की रॉड के स्थान पर सुरक्षित एवं मानक सामग्री का उपयोग किया जाए।कहा कि भी कहा कि गैस सिलेंडर, जनरेटर एवं ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग पूरी सावधानी के साथ करें।टेंटों में अग्निशमन यंत्र एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था अवश्य रखें तथा आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला रखें।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में अयोध्या की बड़ी छलांग, 34वें से 17वें स्थान पर पहुंची रामनगरी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अयोध्या मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित मामलों और विभागीय प्रदर्शन का विस्तृत आकलन किया गया।बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवीनतम

रैंकिंग पर भी चर्चा हुई। इसमें अयोध्या ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 34वें स्थान से छलांग लगाकर 17वां स्थान हासिल किया। अयोध्या को 94.80 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, जिसे प्रशासन ने सकारात्मक उपलब्धि बताया।मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जून माह के आंकड़ों के अनुसार अंबेडकरनगर ने 96.10 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। वहीं सुल्तानपुर ने 95.60 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवां तथा अमेठी ने 95.90 प्रतिशत अंकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया।हालांकि बाराबंकी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। जिले को 92.10 प्रतिशत अंक मिले और वह प्रदेश में 50वें स्थान पर रहा। बैठक में मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा डैशबोर्ड पर प्रदर्शन में लगातार सुधार के लिए समन्वय के साथ कार्य किया जाए।

दीपों की ज्योति से गुरु रविदास को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जन्मोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या महानगर एवं जनपद में विविध धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।भाजपा पदाधिकारी विभिन्न मठ–मंदिरों में पहुंचकर संत–महंतों एवं गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तथा दीपदान और कलश यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं संत परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे। महानगर क्षेत्र के 20 प्रमुख मंदिरों में दीपदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक मंडल में पांच मंदिरों पर 65–65 दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम हनुमानकुंड स्थित गुरु रविदास मंदिर में होगा, जहां 650 दीपों का सामूहिक प्रज्ज्वलन किया जाएगा।इसके साथ ही गुरु रविदास की कर्मस्थली वाराणसी से लाई जा रही पावन मिट्टी के कलश का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन होगा।पूजन के उपरांत इस कलश की यात्रा महानगर के प्रत्येक मंडल एवं शक्ति केंद्रों तक निकाली जाएगी, अभियान सात से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा।

इस अभियान के अंतर्गत महानगर से अभियान सहसंयोजक काशीराम रावत एवं दिनेश कन्नौजिया तथा जिला इकाई से अखंड प्रताप सिंह शडिम्पलश, सुरेन्द्र कोरी, राममोहन भारती, अशोक कसौधन एवं कृष्ण कुमार पाण्डेय श्खुन्नूश मंगलवार देर रात वाराणसी रवाना होंगे। वहां से वे गुरु रविदास की कर्मस्थली की पावन मिट्टी का पूजित कलश अयोध्या लेकर आएंगे।भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का महान पर्व है।उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समाज को समरसता, समानता, श्रम की गरिमा और मानवता का संदेश दिया। भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी अमित कुमार मिश्र ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महानगर के सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।दीपदान,कलश पूजन एवं संत सम्मान कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की योजना बनाई गई है।

तीन साल बाद खुली युवती की हत्या का राज, प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज के मुताबिक पुलिस जांच में जुटी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। करीब तीन वर्ष पूर्व लापता हुई युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है।अंबेडकरनगर पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अयोध्या के थाना महाराजगंज में दर्ज अज्ञात हत्या के मुकदमे का पर्दाफाश हुआ है।पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस के अनुसार, 20 मई 2026 को थाना कोतवाली टांडा में मंगला पत्नी स्वर्गीय हीरालाल, निवासी ग्राम पिपरी मोहम्मदी,ने अपनी पुत्री वंदना के करीब तीन वर्ष पूर्व लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।मामले की जांच के दौरान वादिनी ने सुभाषचंद्र मौर्य निवासी ग्राम डीहा सुल्तान, थाना अलीगंज, जनपद अंबेडकरनगर पर संदेह जताया। 28 जुलाई को पुलिस ने सुभाषचंद्र मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया।पुलिस के दावे के अनुसार, पूछताछ में उसने बताया कि उसके और वंदना के बीच प्रेम संबंध थे तथा युवती तीन माह की गर्भवती हो गई थी।उसने आरोप लगाया कि युवती लगातार उस पर दबाव बना रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने दिसंबर 2023 में उसकी हत्या कर दी।पुलिस के मुताबिक, आरोपी वंदना को अपनी पिकअप गाड़ी से अयोध्या लेकर आया था। दर्शन नगर के पास दोनों के बीच विवाद हुआ। वापसी के दौरान मया बाजार से पहले उसने वाहन को एक सुनसान खड़ंजे वाले रास्ते पर ले जाकर गाड़ी के अंदर वंदना का गला और नाक दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मौत सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर शव पर वाहन दो–तीन बार चढ़ाया और शव को पास के गन्ने के खेत में फेंककर फरार हो गया।पूछताछ में मिली जानकारी के बाद अंबेडकरनगर पुलिस ने थाना महाराजगंज, अयोध्या से संपर्क किया। जांच में पता चला कि इसी घटना के संबंध में थाना महाराजगंज में वर्ष 2024 में अज्ञात के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज था। इसके बाद आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए थाना महाराजगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर ने पुलिस टीम को ₹25 हजार के पुरस्कार की घोषणा की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज देवेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रकरण उनके जानकारी में है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता परेशान, जनप्रतिनिधियों की बेरूखी पर उठ रहे गंभीर सवाल

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।जनपद अयोध्या का मिल्कीपुर क्षेत्र चहुँओर समस्याओ से घिरा है।मूलभूत सुविधाओं के अभाव और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते स्थानीय नागरिकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। चुनावी वादों के पूरा न होने से आहत जनता अब सवाल उठाने पर मजबूर है। घ्जर्जर सड़कें और जलजमावरू क्षेत्र की मुख्य सड़कों और ग्रामीण संपर्कों की हालत खस्ताहाल है।हल्की बारिश में भी जलभराव और कीचड़ के कारण आवागमन बाधित हो जाता है।घ्स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हालरू स्थानीय प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और जरूरी दवाओं की कमी के चलते मरीजों को जिला अस्पताल भागना पड़ता है। बिजली और पानी की किल्लतरू अघोषित बिजली कटौती और पेयजल आपूर्ति में रुकावट से ग्रामीण व व्यापारी वर्ग दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हैं।स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े–बड़े दावे और वादे करने वाले जनप्रतिनिधि अब क्षेत्र की समस्याओं की सुध तक नहीं ले रहे हैं।घ्जब तक चुनाव रहता है, नेता हर चौखट पर सिर झुकाते हैं।चुनाव जीतते ही जनता की सुध लेना बंद कर देते हैं।शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता है, धरातल पर कोई काम नहीं होता।

बिजली संकट पर फूटा गुस्सा, तीन घंटे तक रोकी छह फीडरों की आपूर्ति

भदोही, (संवाददाता)। उमस और गर्मी के बीच बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। त्रिभुवनपुर फीडर से जुड़े 50 से अधिक गांवों के लोगों ने सुबह नौ बजे गिराईं स्थित विद्युत उपकेंद्र गोपीगंज पहुंचकर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने छह फीडरों की आपूर्ति ठप करा दी। सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक 200 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसको लेकर दो पक्ष आमने–सामने आ गए। विद्युत निगम के अधिकारियों के समझाने पर दोपहर एक बजे के बाद आपूर्ति बहाल की गई। गोपीगंज विद्युत उपकेंद्र से कोइरौना, त्रिभुवनपुर समेत छह फीडरों को बिजली आपूर्ति होती है। बीते एक महीने से त्रिभुवनपुर फीडर से जुड़े करीब 50 गांवों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था खराब हो गई है। ट्रिपिंग, अघोषित कटौती के कारण मुश्किल से तीन घंटे बिजली मिल रही थी। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से की, लेकिन सुधार नहीं हुआ। रविवार को सैकड़ो ग्रामीणों ने गोपीगंज विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने उपकेंद्र के सभी छह फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद करा दी। प्रदर्शनकारियों ने पावर हाउस के कमरे में ताला भी जड़ दिया। इससे करीब तीन घंटे तक सभी फीडरों से बिजली आपूर्ति

बिना अल्ट्रासाउंड के ही कर दिया गर्भवती महिला का ऑपरेशन, मौत

भदोही, (संवाददाता)। शाम मधुबन थाना क्षेत्र के कटघराशंकर मोड़ स्थित बिना पंजीकरण के संचालित विमला सदन अस्पताल में शनिवार

की देर शाम ऑपरेशन के बाद गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पति का आरोप है कि अस्पताल में बिना समुचित जांच और आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाए ही डॉक्टरों ने अफसाना की निर्धारित अवधि पूरी होने से करीब डेढ़ महीने पहले ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड जांच भी नहीं कराई गई। रविवार को इस मामले की सूचना मिलने पर एसीएमओ डॉ. आरएन सिंह अस्पताल पहुंचे। जांच में कोई दस्तावेज न मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया। फतेहपुर मंडाव सीएचसी और मधुबन पीएचसी के बीच बिना लाइसेंस के संचालित अस्पताल की विभागीय मॉनीटरिंग पर सवाल प्रश्न चिह्न लगा रहा है। तिघरा निवासी पति इंतजार अहमद ने बताया कि उसका निकाह तीन वर्ष पहले अफसाना से हुई थी। बताया कि उसकी एक बेटी है। पत्नी के गर्भवती होने पर वह विमला सदन में उपचार करा रहा था। शनिवार को पेट में दर्द होने पर वह मधुबन स्थित विमला सेवा सदन अस्पताल लेकर पत्नी को गया था। बताया कि ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद अफसाना की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे मऊ स्थित एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चिकित्सकों ने मरीज की गंभीर स्थिति देखते हुए जवाब दे दिया। इसके बाद उसे दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से भी भर्ती करने से मना कर दिया गया।

अधेड़ का मिला शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

गोरखपुर, (संवाददाता)। हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तुलसीरतन गांव के सिवान में रविवार दोपहर करीब 50 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के चेहरे और पेट पर खून के निशान मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्याकर शव को यहां फेंके जाने की आशंका जताई है। देर शाम तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। ग्रामीणों के अनुसार, रविवार दोपहर कुछ लोग खेत की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर एक व्यक्ति के शव पर पड़ी। शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा था और चेहरे व पेट पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने सोनबरसा पुलिस चौकी को सूचना दी।

प्रेमी युगल की ट्रेन से कटकर मौत, रेलवे ट्रैक पर मिले शव-प्रेम संबंध की आशंका

गोरखपुर, (संवाददाता)। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे नवीन सब्जी मंडी सरैया के पास शुक्रवार रात एक युवक और युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के बीच पड़े मिले थे। उन्हें अलग–अलग एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने और आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8रू10 बजे किसी व्यक्ति के ट्रेन से कटने की सूचना मिली। सूचना पर रेलवे सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद ट्रैकमैन अभय कुमार यादव और हनुमंत कुमार यादव ने बताया कि रात करीब 8:15 बजे उन्होंने एक युवक और एक युवती को अप लाइन के बीच गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा। दोनों को ट्रैक से हटाकर रेल लाइन

खाली कराई गई, ताकि रेल यातायात प्रभावित न हो। घटना की सूचना पर डायल–112 और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पहले युवती को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इसके बाद दूसरी एंबुलेंस से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सक डॉ. इसरार अहमद ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उसके मोबाइल पर आए फोन के आधार पर हुई। उसके भाई मोहन साहनी ने उसकी पहचान अर्जुन साहनी (20) पुत्र रामसूरत साहनी, निवासी लीलाहवा ओला, थाना कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर के रूप में की। वहीं युवती की पहचान लक्ष्मीना (18) निवासी बखिरा चिरैयाड़ाड, थाना बखिरा, संतकबीरनगर के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों परिवारों के लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवीन मंडी चौकी पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी रही। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम संबंध में आत्मघाती कदम उठाने का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना के बावजूद रेल परिचालन प्रभावित नहीं हुआ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।